सभी फोटो: आशीष अग्निहोत्री

◄ **स्वदेशी सुविधा** आगरा में फुटवियर और लेदर टेस्टिंग लैबोरेटरी

▼ **पुराना काम** संभल की एक इकाई में जानवरों की सींग से बटन का निर्माण

संकट में ही निकला समाधान

उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्र एमएसएमई पर दिया विशेष ध्यान. नतीजा: महामारी के दौरान कारोबार के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़े

आशीष मिश्र

पश्चिमी यूपी के संभल जिले की पहचान यहां भैंस की सींग से बनने वाले हैंडीक्राफ्ट से रही है. पिछले 50 वर्षों से यहां पर भैंस की सींग से शर्ट में लगने वाले बटन बनाने का काम हो रहा है. संभल से कच्चा बटन चीन की कंपनियां खरीद लेती हैं. ये कंपनियां इन बटन की बेहतर फिनिशिंग करके अमेरिका, यूरोप और भारत में महंगे दामों पर निर्यात करती हैं. भारत के साथ बढ़ते विवाद के चलते संभल ने चीन के साथ सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ लिए हैं. यहां के व्यापारियों ने अपना कच्चा माल चीनी कंपनियों को बेचने से मना कर दिया है. व्यापारियों के जज्बे को देखते हुए यूपी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) विभाग ने संभल जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर सरायतरीन इलाके में बटन की फिनिशिंग के लिए अत्याधुनिक विदेशी मशीनें लगाने की तैयारी शुरू कर दी है. करीब 10 करोड़ रु. वाले इस प्रोजेक्ट में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 9 करोड़ रु. और स्थानीय उद्यमियों ने जमीन के साथ बाकी एक करोड़ रु. का इंतजाम किया है. संभल के बड़े बटन व्यवसायी शोएब यूसुफ कहते हैं, "देश-विदेश में जो महंगे चाइनीज बटन बिकते थे वे सभी कच्चे रूप में संभल से ही खरीदे जाते थे. संभल में भी फिनिशिंग की आधुनिक मशीनें लग जाने के बाद यहां के बटन पूरी दुनिया में धूम मचाएंगे. इससे संभल को पूरे विश्व में नई पहचान मिलेगी."

संभल से करीब 300 किलोमीटर दूर ताजनगरी आगरा में चमड़ा व्यवसाय से जुड़े उद्योगपति वर्षों से अपने उत्पादों की जांच के लिए चेन्नै या फ्रांस-जर्मनी की प्रयोगशालाओं का मुंह ताकते थे. बाहरी लैब की जांच में न केवल समय अधिक लगता था बल्कि यह पूरी प्रक्रिया काफी खर्चीली भी थी. 'उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना' के तहत आगरा-मथुरा हाइवे पर 21 किलोमीटर दूर सिंगना इलाके में देश की अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब बनाई गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 अगस्त को इस लैब का लोकार्पण किया और इसके साथ ही आगरा के चमड़ा व्यवसाइयों की दौड़भाग को भी विराम लगा. आगरा के मशहूर चमड़ा व्यवसायी पूरन डावर बताते हैं, "लेदर, फुटवियर कंपोनेंट, गारमेंट और टेक्सटाइल में एक हजार तरह की हाइ रिस्क केमिकल और फिजिकल जांच की विश्वस्तरीय सुविधा शुरू होने से आगरा से चमड़ा उत्पादों के निर्यात में तेजी आएगी." साढ़े पंद्रह करोड़ रु. की इस लैब के लिए धनराशि का 80 फीसद हिस्सा राज्य सरकार ने दिया है. स्थानीय उद्योगपतियों ने जमीन के साथ बाकी 20 प्रतिशत राशि का इंतजाम किया है.

कोरोना संक्रमण के दौरान बने माहौल में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में एमएसएमई की फौज का इस्तेमाल प्रदेश के औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाकर रोजगार की संभावनाएं पैदा करने के लिए कर रहे हैं. नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) के 73वें (2015-16) राउंड के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, यूपी में ऑन एकाउंट एंटरप्राइज (ओएई), मतलब ऐसे उद्यम जो एक भी कर्मचारी को नौकरी पर रखे बगैर चल रहे हैं, की कुल संख्या 78,74,711 है. 'एस्टैब्लिशमेंट', यानी ऐसे उद्यम जिनमें कम से कम एक कर्मचारी को नौकरी मिली है, की संख्या 11,25,051 है. वहीं केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय में 'उद्योग आधार मेमोरेंडम' (यूएएम) के तहत यूपी में रजिस्टर्ड इकाइयों की संख्या 8,92,029 है. एमएसएमई की इतनी बड़ी संख्या के बल पर यूपी सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को तेज करना चाहती है.

आर्थिक पैकेज की संजीवनी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच 12 मई को लॉकडाउन चौथी बार बढ़ाने की घोषणा के साथ 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के लिए 20 लाख करोड़ रु. के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था. प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज की घोषणा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई विभाग के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और तत्कालीन प्रमुख सचिव (अब अपर मुख्य सचिव) एमएसएमई नवनीत सहगल को आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ यूपी के उद्यमियों दिलाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया था. लोकभवन के सी ब्लॉक के पहले तल पर बैठने वाले एमएसएमई विभाग के अपर मुख्य सचिव सहगल ने पूरी रात अपना दफ्तर खोलकर बैंक और उद्यमियों के बीच समन्वय स्थापित किया. प्रधानमंत्री की घोषणा के महज 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री ने यूपी के 56,754 एमएसएमई उद्यमियों को 2002.49 करोड़ रु. के ऑनलाइन ऋण वितरित किए. इस प्रकार लॉकडाउन अवधि में उद्यमियों को इतनी बड़ी संख्या में ऋण वितरित करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया. इसी दिन 14 मई को मुख्यमंत्री ने लोगों को रोजगार दिलाने के लिए ऑनलाइन 'स्वरोजगार संगम' कार्यक्रम का भी आयोजन किया. इसमें 56,754 एमएसएमई इकाइयों में करीब दो लाख से अधिक कामगारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए. एमएसएमई विभाग 'ऑन एकाउंट एंटरप्राइज' और 'एस्टैब्लिशमेंट' श्रेणी के उद्यमों में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार दिलाने की व्यवस्था कर कुल 90 लाख रोजगार करने की दिशा में भी कार्यवाई कर रहा है. एमएसएमई विभाग यूपी में अब तक 2,71,473 नई इकाइयों को 8,949 करोड़ रु. का ऋण बैंकों के सहयोग से वितरित करा चुका है.

> **"देश-विदेश में जो महंगे चाइनीज बटन बिकते थे वे सभी कच्चे रूप में संभल से ही खरीदे जाते थे. यहां फिनिशिंग की आधुनिक मशीनें लग जाने के बाद यहां के बटन पूरी दुनिया में धूम मचाएंगे."**
>
> **शोएब यूसुफ, बटन व्यवसायी**

उद्योगों को ऑनलाइन प्लेटफार्म

लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 7 अगस्त को एमएसएमई विभाग की ओर से संचालित हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए प्रशिक्षण योजना और 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओपी)-विपणन योजना की ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत की. उद्योगों को अधिक से अधिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ई-बे के साथ समझौता किया गया है. एमएसएमई विभाग की बदली कार्यप्रणाली के मुख्य आर्किटेक्ट अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल बताते हैं, "एमएसएमई विभाग की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने से उद्यमियों